

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

[2023] 8 एस. सी. आर 828

क.

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. और ए. एन. आर.

वी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी और ओआरएस। (2011 की सिविल अपील संख्या 2297)

12 मई, 2023

**[एम. आर. शाह और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]**

सिद्धांत/सिद्धांत-वैध अपेक्षा का सिद्धांत-पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994।2(17), 17(3)(क) (xi), 39-पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2001-पश्चिम बंगाल बिक्री कर नियम, 1995 -आर. 52-बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941-एस 2 (डीडी)-चाहे एस के बावजूद।2(17) 1994 के अधिनियम में, जिसे डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.2001 में संशोधित किया गया था, "चाय मिश्रण" को "निर्माण" की परिभाषा से हटाकर, अपीलार्थी अभी भी बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार होंगे-धारित:एम. आर. शाह के अनुसार, जे. कोई भी छूट का दावा अधिकार के मामले के रूप में नहीं कर सकता है-छूट देना/जारी रखना/वापस लेना एक नीतिगत निर्णय है-जब तक कि वापसी इतनी मनमानी नहीं पाई जाती है, तब तक अदालत हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगी-2001 से पहले, एस के अनुसार।2(17), 1994 अधिनियम, "चाय मिश्रण" की गतिविधि को "निर्माण" की परिभाषा में शामिल किया गया था-इसलिए, "चाय मिश्रण" की गतिविधि में होने के कारण, अपीलकर्ता निर्माताओं के रूप में बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार थे-हालांकि, संशोधन के परिणामस्वरूप, जब "चाय मिश्रण" की गतिविधि को "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया था, तो अपीलकर्ता निर्माता नहीं रह गए और इस प्रकार, 01.08.2001 पर और उससे, वे छूट के हकदार नहीं थे-कानून के खिलाफ कोई वचन-भंग नहीं हो सकता है-यह "निहित अधिकार" का मामला नहीं है, बल्कि "मौजूदा अधिकार" का मामला है, जिसे परिवर्तित या संशोधित और/या वापस लिया जा सकता है-न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विचार - [असहमति (वैध अपेक्षा के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर)] चाय के निर्माण और मिश्रण में शामिल छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए एक संशोधन के माध्यम से दी गई छूट ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक वैध अपेक्षा पैदा की-यह वैध अपेक्षा तब टूट गई जब बाद में एक संशोधन लाया गया जिसमें "निर्माण" की परिभाषा से "चाय के मिश्रण" को हटा दिया गया-नीति में इस तरह के बदलाव को उचित ठहराने के लिए, और अपीलकर्ताओं के पक्ष में बनाई गई वैध अपेक्षा को छीनने के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरण को चाहिए कि वह

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

828 ए.

829

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुरी ए

इस तरह के बदलाव के कारणों को प्रदर्शित करें-हालांकि, ऐसा कोई उचित औचित्य प्रदान नहीं किया गया था-सरकार में निहित सबूत के बोझ का निर्वहन करने के लिए नीति में परिवर्तन का केवल दावा पर्याप्त नहीं था-प्रत्यर्थियों को मूल संशोधन के लाभ अपीलार्थियों को मूल संशोधन के अनुसार ऐसे लाभ की समाप्ति तक बढ़ाने के लिए-राय के विचलन को देखते हुए, उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना-कुटीर और लघु उद्योग के लिए प्रोत्साहन की राज्य योजना, 1993-पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजना, 1999।मनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और

ओआरएस। (2016) 6 एससीसी 766:[2016] 3 एससीआर 718; एमआरएफ लिमिटेड,

ग

कोट्टायम बनाम सहायक आयुक्त (मूल्यांकन) बिक्री

कर और अन्य। (2006) 8 एससीसी 702:[2006] 6 पूरक।एससीआर

**417**; मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनामकी स्थिति

उत्तर प्रदेश और अन्य। (1979) 2 एससीसी 409:[1979] 2

एससीआर **641**; झारखंड राज्य और अन्य बनामब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड रांची और अन्न। सिविल अपील सं। **2020** का **3860-3862**; दाई-इची करकरिया लिमिटेड बनाम.भारत संघ

डी.

& ओआरएस। (2000) 4 एससीसी 57:[2000] 2 एस. सी. आर. 1254-लागू नहीं हुआ।

फिल्म समारोह और अन्य निदेशालय बनामगौरव अश्विन

जैन और ओआरएस। (2007) 4 एससीसी 737:[2007] 5 एस. सी. आर. 7-संदर्भित।

ई.

न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति बनाम संघ

भारत और ओआरएस। (1991) 4 एससीसी 699:[1991] 2 पूरक।एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

च

केरल राज्य और अन्य बनामके. जी. माधवन पिल्लई और अन्य।

(1988) 4 एससीसी 669:[1988] 3 पूरक।एस. सी. आर. 94; नवज्योति

कॉप।ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एंड ओआरएस. वी.भारत संघ

& ओआरएस। (1992) 4 एससीसी 477:[1992] 1 पूरक।एससीआर 709;

भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनू पशु आहार

उद्योग (1993) 1 एस. सी. सी. 71:[1992] 2 पूरक।एससीआर 322;

जी.

एम. पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ए. एन. आर. बनामएम. पी. और अन्य की स्थिति।

(1997) 7 एससीसी 592:[1997] 1 पूरक।एससीआर 671; एमआरएफ

लिमिटेड कोट्टायम बनाम सहायक आयुक्त बिक्री कर और

ओआरएस। (2006) 8 एससीसी 702:[2006] 6 पूरक।एस. सी. आर. 417;

हावड़ा नगर निगम और अन्य बनामगंगा की रस्सी

एच.

830 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2004) 1 एससीसी 663:[2003] 6

पूरक।एससीआर **1212**; मद्रास सिटी वाइन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन और ए. एन. आर. बनामतमिलनाडु राज्य और अन्न।  
**(1994)**

**5 एससीसी 509:[1994] 2 पूरक।एस. सी. आर. 281-संदर्भित।**

आर बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त, एम. एफ. के. अंडरवर्टिंग एजेंट्स लिमिटेड [1982] एसी 617; आर. (बैनकोल्ट) बनाम विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव) [1990] 1 डब्ल्यूएलआर 1545; श्मिट बनाम गृह मामलों के राज्य सचिव [1969] 2 डब्ल्यूएलआर 337; ओ 'रेली बनाम मैकमैन [1983] 2 एसी 237; सिविल सेवा संघों की परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री [1984] 3 डब्ल्यूएलआर 1174; आर. बनाम उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण, पूर्व पक्ष कफलन [2001] क्यू. बी. 214; नादराजा बनाम गृह राज्य सचिव

ग

विभाग [2005] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 1363-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

डी.

एम. आर. शाह के निर्णय में, जे.

**[2016] 3 एस. सी. आर. 718 पैरा 4.6 [2006] 6 अनुपूरक लागू नहीं हुआ।एस. सी. आर. 417 लागू नहीं हुआ पैरा 4.6 [1979] 2 एस. सी. आर. 641 लागू नहीं हुआ पैरा 4.6 [2000] 2 एस. सी. आर. 1254 लागू नहीं हुआ पैरा 4.7 [2007] 5 एस. सी. आर. 7**

ई.

संदर्भित किया गया है

पैरा **5.7**

कृष्ण मुरारी के फैसले में, जे. **[1991] 2 सप्लीमेंट।एस. सी. आर. 1** का अनुसरण किया गया

पैरा **13 [1988] 3 पूरक।एस. सी. आर. 94 पैरा 21 [1992] 1 सप्लीमेंट** को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **709 पैरा 22 [1992] 2 सप्लीमेंट** को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **322 पैरा 23 [1997] 1 सप्लीमेंट** को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **671 पैरा 24 [2006] 6 सप्लीमेंट** को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **417 पैरा 26 [2003] 6 सप्लीमेंट** को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **1212 पैरा 27 [1994] 2 सप्लीमेंट** को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **281 पैरा 27 ए. में निर्दिष्ट है।**

च

जी.

एच.

831

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुरी ए

सिविल अपील न्यायनिर्णय: 2011 की सिविल अपील सं. 2297।

2006 के डब्ल्यू. पी. टी. टी. सं. 479 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 18.03.2008 के निर्णय और आदेश से।

सह

2011 की सिविल अपील संख्या 2301, 2305, 2298, 2300, 2299, 2302, 2303 और 2304।

सुश्री कविता झा, शम्मी कपूर, अदित्य बाली, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

ग

सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य, उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता। न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

एम. आर. शाह, जे.

1. कलकत्ता में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित रिट याचिकाओं में पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

डी.

2. जैसा कि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है, इन सभी अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जा रहा है और उनका निपटारा किया जा रहा है। सुविधा के लिए, 2006 की रिट याचिका संख्या 479 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न 2011 की सिविल अपील संख्या 2297 को प्रमुख मामले के रूप में माना जाए। संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:- 2.1 पूर्ववर्ती बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 (इसके बाद "अधिनियम, 1941" के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (डी. डी.) ने "निर्माण" और "किसी भी वस्तु का मिश्रण" शब्द को परिभाषित किया था, जिसे उक्त परिभाषा में शामिल किया गया था। कि अधिनियम, 1941 को पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994 (इसके बाद "अधिनियम, 1994" के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और अप्रैल, 1998 के महीने में अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के तहत प्रदान की गई "निर्माण" की परिभाषा में संशोधन किया गया और जिसके परिणामस्वरूप, "किसी भी वस्तु के मिश्रण" को "निर्माण" की परिभाषा से हटा दिया गया था, लेकिन "चाय के मिश्रण" को उक्त परिभाषा में शामिल किया जाता रहा।

ई.

च

जी.

एच.

832

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

2.2 अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के तहत प्रदान की गई "विनिर्माण" की परिभाषा में किए गए संशोधन के आधार पर, पश्चिम बंगाल बिक्री कर नियम, 1995 (इसके बाद "नियम, 1995" के रूप में संदर्भित) के नियम 52 के साथ अधिनियम, 1994 की धारा 17 (3) (ए) (xi) के साथ पठित अधिनियम, 1994 की धारा 39 के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए नई लघु औद्योगिक इकाइयों को कर अवकाश दिया गया था।

2.3 तत्पश्चात, कुटीर और लघु-स्तरीय उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की राज्य योजना, 1993 (1993 योजना) में वर्ष 1999 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा संशोधन किया गया था, जिससे पश्चिम बंगाल राज्य में बड़े, मध्यम और लघु औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजना, 1999 (जिसे इसके बाद "1999 योजना" के रूप में संदर्भित किया गया है) को लागू किया गया, जो पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी है। 2.4 1999 की योजना के प्रावधानों के अनुसार, 1999 की योजना के तहत प्रदान की गई सभी आवश्यकताओं का पालन करने के बाद स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाइयों को उक्त इकाइयों में विनिर्माण गतिविधि के लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट दी गई थी।

ग

डी.

2.5 अपीलार्थियों की ओर से यह मामला है कि उक्त योजना और अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के तहत "निर्माण" की परिभाषा में किए गए संशोधन पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थियों ने मिश्रित चाय के निर्माण का व्यवसाय करने के उद्देश्य से एक नई लघु औद्योगिक इकाई की स्थापना की थी।

ई.

2.6 1999 की योजना के प्रावधानों के अनुसार, छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए, नियमों, 1995 के नियम 55 के साथ पठित धारा 39 के अनुसार खुद को छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाई के रूप में पंजीकृत करना और बिक्री कर विभाग से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। उपायुक्त ने अपीलार्थियों को विनिर्मित उत्पाद की पहली बिक्री की तारीख से सात साल की अवधि के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया। अपीलार्थियों को अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) और धारा 39 के तहत दो साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ तब तक मिला जब तक कि पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा धारा 2 (17) में संशोधन नहीं किया गया। अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) को पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित किया गया, जिसके तहत अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के तहत प्रदान की गई "निर्माण" की परिभाषा से "चाय का मिश्रण" शब्दों को हटा दिया गया था। नतीजतन, बिक्री कर के भुगतान से छूट, जो ए था

च

जी.

एच.

833

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुरी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अपीलार्थियों को दिए गए आवेदन को रोक दिया गया और यहां तक कि पात्रता प्रमाण पत्र को भी संशोधित करने की आवश्यकता थी।

2.7 उपरोक्त कार्रवाई/आदेश को पहले न्यायाधिकरण के समक्ष और उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने आवेदन को खारिज कर दिया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले और आदेश द्वारा की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है, जिसमें पहले की 1999 की योजना के अनुसार बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा किया गया है। 3. अपीलार्थियों की ओर से विद्वत वकील सुश्री कविता झा पेश हुईं और प्रत्यर्थियों-राज्य की ओर से विद्वत वकील सुश्री मधुमिता भट्टाचार्य पेश हुईं।

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की थीं:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

4.1 यह कि अपीलकर्ताओं को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति पर एक अवधि के लिए कर का लाभ प्राप्त करने की उम्मीद में नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए लुभाया गया था और एक बार ऐसी आवश्यकताओं के आधार पर ऐसी औद्योगिक इकाई को ऐसा लाभ दिया जाता है, बाद में, संशोधन के माध्यम से ऐसा अधिकार नहीं लिया जा सकता है। 4.2 यह कि राज्य प्राधिकरण ने इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि अपीलकर्ताओं ने सात साल की अवधि के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और पहले ही एक विशेष अवधि के लिए योजना का लाभ उठा चुके थे, अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के तहत "निर्माण" की परिभाषा से "चाय का मिश्रण" शब्द को पूरी तरह से हटा दिया है। जिस दिन से अधिनियम, 1994 के तहत पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, उस दिन से अपीलार्थियों के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया था और राज्य द्वारा इस लाभ को रद्द करने का एकमात्र उचित तरीका व्यापक जनहित दिखाना था। वर्तमान मामले में भी, धारा 2 (17) में किए गए संशोधन को उचित ठहराने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई व्यापक सार्वजनिक हित नहीं दिखाया गया है।

डी.

ई.

च

4.3 कि वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है जहां कानून के प्रावधान के तहत संशोधन जनहित के अनुरूप नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उत्तरदाता लाभों को रद्द करने में कोई सार्वजनिक हित प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।

जी.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि इस मामले में, अपीलार्थियों को परिभाषा में किए गए संशोधन के कारण लाभ से वंचित कर दिया गया था

एच.

834

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

"अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के तहत "विनिर्माण" जो राज्य द्वारा किसी भी सार्वजनिक हित को शामिल किए बिना एक मनमाना कदम है। इसलिए, मनमाने तरीके से लिया गया कोई भी निर्णय वैध अपेक्षा के सिद्धांत के विपरीत है, अगर मामले में शामिल सार्वजनिक हित को विशेष रूप से दिखाए बिना लिया जाता है।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में राज्य की कार्रवाई तर्क और प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरती है, क्योंकि राज्य द्वारा लाभों को रद्द करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं ने योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति में बदलाव किया था और लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन की थी। 18,12,967-और लगभग रु। 65,00,000-के. बी. टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में और चूंकि, अपीलकर्ताओं ने योजना के तहत लाभों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त खर्च किए थे, इसलिए राज्य ऐसे लाभों को तब तक नहीं ले सकता जब तक कि कुछ प्रमुख सार्वजनिक हित शामिल न हों। राज्य द्वारा

किया गया उक्त कार्य अनुचित है और अपीलार्थियों के खिलाफ शक्ति का दुरुपयोग है।रिलायंस को निम्नलिखित निर्णयों पर रखा गया है:

ग

डी.

मनुएलसन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य, **(2016) 6 एस. सी. सी. 766**; एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम सहायक आयुक्त (मूल्यांकन) बिक्री कर और अन्य, **(2006) 8 एस. सी. सी. 702** और मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, **(1979) 2 एस. सी. सी. 409**।

ई.

4.7 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है झारखंड और ओआरएस। बनाम ब्रह्मपुत्र मेटालिक्स लिमिटेड, रांची और अन्न। [दीवानी अपील सं. **2020** का **3860-3862**] और दाई-इची करकरिया लिमिटेड के मामले में। बनाम भारत संघ और अन्य, **(2000) 4 एस. सी. सी. 57** में

च

वैध अपेक्षा पर प्रस्तुत करने का समर्थन।4.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए।

5. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी छूट के हकदार नहीं होंगे जैसा कि दावा किया गया है।

जी.

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 1999 में, अपीलकर्ताओं को अधिनियम, 1994 की धारा 39 के तहत ए की पहली बिक्री की तारीख से सात साल की अवधि के लिए कर अवकाश के लिए पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया था।

एच.

835

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुरी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

उस समय अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) में "विनिर्माण" की परिभाषा में "चाय का मिश्रण" शामिल था।

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में, अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के तहत "निर्माण" की परिभाषा को पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित किया गया और "चाय के मिश्रण" को डब्ल्यू. ई. एफ. की परिभाषा से हटा दिया गया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम, 1994 के तहत एक निर्माता नहीं रह गई और इसलिए, अधिनियम, 1994 की धारा 39 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलीगुड़ी प्रभार ने संशोधन के संदर्भ में अपीलकर्ता कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन करने की मांग की।

ग

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले विनिर्माण गतिविधियों में लगी लघु औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रासंगिक समय पर, pre-01.08.2001, और अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के अनुसार, "चाय का मिश्रण" को "निर्माण" की परिभाषा में शामिल किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, निर्माता होने के नाते, अपीलकर्ताओं को छूट की अनुमति दी गई थी।हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद, अधिनियम, 1994 डब्ल्यू.

ई. एफ. की धारा 2 (17) में संशोधन को देखते हुए, "चाय के मिश्रण" को "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया था और इसलिए, अपीलकर्ताओं का निर्माता बनना बंद हो गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब अपीलकर्ता निर्माता नहीं रह जाते हैं, तो अपीलकर्ता छूट के हकदार नहीं होंगे क्योंकि छूट केवल विनिर्माण गतिविधियों में लगी लघु औद्योगिक इकाइयों और अधिनियम, 1994 के तहत निर्माता के लिए उपलब्ध थी।

डी.

ई.

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब विधायिका ने अपने विवेक से "चाय मिश्रण" को "निर्माण" की परिभाषा से बाहर कर दिया है, तो "चाय मिश्रण" को एक विनिर्माण गतिविधि के रूप में नहीं माना जा सकता है जो अधिनियम, 1994 की धारा 39 द्वारा प्रदान की गई छूट का आनंद लेने का हकदार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वैध अपेक्षा पर अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करना और अपीलकर्ताओं के पक्ष में धारा 2 (17) "निहित अधिकार" में संशोधन करके इसे छीन नहीं लिया जा सकता था, इसमें कोई सार नहीं है।

च

जी.

5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, यह "निहित अधिकार" का मामला नहीं है, बल्कि "मौजूदा अधिकार" का मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, मौजूदा अधिकार को छीन लिया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी कानून के खिलाफ कोई वैध अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

एच.

836

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

5.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि छूट देना या न देना एक नीतिगत निर्णय है और कोई भी अधिकार के रूप में छूट का दावा नहीं कर सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, विद्वान न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थियों को बिक्री कर के भुगतान से कोई छूट देने से इनकार कर दिया है जो अपीलार्थियों को "चाय मिश्रण" के निर्माता होने से पहले दी जा रही थी।

5.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह पूर्वव्यापी संचालन का मामला नहीं है, बल्कि यह बिक्री कर की छूट प्राप्त करने के मौजूदा निरंतर अधिकार की संभावित वापसी का मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब विधायिका ने अपने विवेक से धारा 2 (17) में निहित "निर्माण" की परिभाषा में संशोधन किया और "चाय मिश्रण" को "निर्माण" की परिभाषा से बाहर कर दिया गया और जिसके परिणामस्वरूप छूट वापस ले ली गई, जिसे अपीलार्थी निर्माता के रूप में 01.08.2001 से पहले प्राप्त कर रहे थे, एक नीतिगत निर्णय होने के कारण, यह न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। रिलायंस को इस मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है

ग

फिल्म समारोह और अन्य निदेशालय। बनाम गौरव अश्विन जैन और अन्य, (2007) 4 एससीसी 737।

डी.

5.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना। 7. इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त प्रश्न है: ई.

“क्या पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के बावजूद, जिसे पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.2001 में संशोधित किया गया था, जिसमें “विनिर्माण” की परिभाषा से “चाय मिश्रण” को हटा दिया गया था, फिर भी अपीलकर्ता बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार होंगे?

च

8. अपीलार्थियों की ओर से मुख्य निवेदन यह है कि 01.08.2001 से पहले, अपीलार्थी बिक्री कर छूट का लाभ उठा रहे थे, उक्त अधिकार को अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) में संशोधन के आधार पर वैध अपेक्षा के साथ-साथ प्रतिज्ञात्मक रोक द्वारा नहीं लिया जा सकता था। इस प्रकार, अपीलार्थियों की ओर से यह मामला है कि अधिनियम, 1994 के तहत, जब अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) में संशोधन किया गया था, अपीलार्थियों को एक “निहित अधिकार” था और इसलिए, अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) में संशोधन बिक्री कर के भुगतान से छूट के ऐसे “निहित अधिकार” को प्रभावित नहीं करेगा, जिसे अपीलार्थी पहले प्राप्त कर रहे थे।

जी.

एच.

837

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

8.1 हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा करने का मामला है। कानून की तय स्थिति के अनुसार, कोई भी अधिकार के रूप में छूट का दावा नहीं कर सकता है। छूट हमेशा छूट का लाभ उठाने की शर्तों को पूरा करने पर होती है और इसे राज्य द्वारा वापस लिया जा सकता है। छूट देना और/या छूट जारी रखना और/या वापस लेना हमेशा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है और यह नीतिगत निर्णय के भीतर आता है और कानून की तय स्थिति के अनुसार, जब तक कि वापसी इतनी मनमाना नहीं पाई जाती है, तब तक अदालत ऐसे नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगी। 8.2 वर्तमान मामले में, 2001 से पहले, अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के अनुसार, “चाय मिश्रण” की गतिविधि को “निर्माण” की परिभाषा में शामिल किया गया था। इसलिए, “चाय मिश्रण” की गतिविधि में होने के कारण, अपीलार्थी निर्माताओं के रूप में बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार थे। यह विवादित नहीं हो सकता है कि “चाय मिश्रण” की गतिविधि में निर्माता होने के नाते अपीलार्थी हमेशा बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार रहे होंगे। एक निर्माता होने के नाते, “चाय मिश्रण” की गतिविधि में होने के कारण, अपीलार्थी बिक्री कर छूट का लाभ उठा रहे थे। हालाँकि, इसके बाद, अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) में निहित “निर्माण” की परिभाषा को पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2001 के माध्यम से डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.2001 में संशोधित किया गया और “चाय मिश्रण” की गतिविधि को “निर्माण” की परिभाषा से बाहर रखा गया। नतीजतन, अपीलकर्ताओं का निर्माता बनना बंद हो गया। एक बार जब अपीलार्थी निर्माता नहीं रह जाते हैं, तो अपीलार्थी बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार नहीं होंगे, जो “चाय मिश्रण” की गतिविधि में एक निर्माता के रूप में अपीलार्थी के लिए उपलब्ध था। इसलिए, 01.08.2001 पर और उससे, “चाय मिश्रण” गतिविधि विनिर्माण गतिविधि के रूप में समाप्त हो गई और अपीलार्थी निर्माता नहीं रह गए और इसलिए, 01.08.2001 पर और उससे, अपीलार्थी बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार नहीं होंगे। इस प्रकार, बिक्री कर के भुगतान से छूट की वापसी संभावित होगी न कि पूर्वव्यापी। जब तक अपीलार्थी अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) के अनुसार निर्माता बने रहते हैं, तब तक अपीलार्थी को बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ पाने का हकदार कहा जा सकता है क्योंकि निर्माता “चाय मिश्रण” की गतिविधि में हैं। जिस क्षण “चाय मिश्रण” गतिविधि विनिर्माण गतिविधि के रूप में समाप्त हो जाती है, उस दिन और उसके बाद से, अपीलार्थी बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार नहीं होंगे।

ग

डी.

ई.

च

जी.

8.3 अब, जहाँ तक अपीलकर्ताओं की ओर से वैध अपेक्षा और/या वचन-निरसन और उस पर प्रस्तुत करने की बात है।

एच.

838

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

अपीलार्थियों की ओर से कि "निहित अधिकार" को हटाया नहीं जा सकता है, इसका संबंध है, उपरोक्त में कोई सार नहीं है। कानून की तय की गई स्थिति के अनुसार कानून के खिलाफ कोई वचन बहिष्कार नहीं हो सकता है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, यह "निहित अधिकार" का मामला नहीं है, बल्कि "मौजूदा अधिकार" का मामला है, जिसे बदला जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है और/या वापस लिया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) में निहित परिभाषा में संशोधन के अनुसार डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.2001 जिसके द्वारा "चाय मिश्रण" गतिविधि को "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया है और इसलिए, उस दिन और उसी दिन से, अपीलार्थी निर्माता नहीं रह गए और वे बिक्री कर के भुगतान से छूट के लाभ के हकदार नहीं होंगे जैसा कि निर्माताओं के रूप में उनके लिए उपलब्ध था।

ग

8.4 इस स्तर पर, यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिनियम, 1994 की धारा 39 के अनुसार, जिसके तहत अपीलकर्ता बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा कर रहे हैं, एक व्यापारी द्वारा उस अवधि के लिए कोई कर देय नहीं होगा जो उसके द्वारा निर्मित उसकी बिक्री-वस्तुओं के संबंध में निर्धारित की जाए। इसलिए, "निर्माण" शब्द बहुत प्रासंगिक है और यह एक ऐसी शर्त है जिसे पूरा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, "निर्माण" की परिभाषा वास्तव में प्रासंगिक है। इसलिए, यदि कोई विक्रेता निर्माता नहीं रह जाता है, तो वह धारा 39 के तहत छूट का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा। धारा 39 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"39. नई लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए कर अवकाश-(1)

ई.

ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, जो निर्धारित की जाए, एक व्यापारी द्वारा निर्धारित क्षेत्र में स्थित अपनी नव स्थापित लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाई में उसके द्वारा निर्मित माल की बिक्री के संबंध में और धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत बिक्री के अपने कर योग्य कारोबार की गणना करने में ऐसी अवधि के लिए कोई कर देय नहीं होगा, कि बिक्री के उसके सकल कारोबार का वह हिस्सा जो ऐसी वस्तुओं की बिक्री के कारोबार का प्रतिनिधित्व करता है, उस धारा की उप-धारा (3) के खंड (ए) के उप-खंड (viii) के तहत बिक्री के उसके सकल कारोबार से काट लिया जाएगा।XXXXXXXXXXXX "

च

जी.

8.5 इन परिस्थितियों में, ऊपर निर्दिष्ट अपीलार्थियों की ओर से लिए गए निर्णय, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, मैं विद्वान न्यायाधिकरण के साथ-साथ ए द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूँ।

एच.

839

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुरी ए

उच्च न्यायालय के रूप में कि अधिनियम, 1994 की धारा 2 (17) में संशोधन, जिसके द्वारा "निर्माण" की परिभाषा में संशोधन किया गया है और "चाय मिश्रण" को "निर्माण" की परिभाषा से बाहर रखा गया है, के बाद और उसके बाद अपीलार्थी बिक्री कर के भुगतान से छूट के हकदार नहीं होंगे।

इन परिस्थितियों में, ये सभी अपील विफल हो जाती हैं और वे खारिज किए जाने के योग्य होती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, खर्चे बाबत कोई आदेश नहीं होगा।

कृष्णा मुरारी, न्या.

ग

1. मुझे अपने सम्मानित भाई, माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह द्वारा प्रस्तावित निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है। हालाँकि, मैं अपने सम्मानित भाई द्वारा दिए गए तर्क और परिणाम से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, और इस प्रकार अपने निष्कर्ष को अलग से लिख रहा हूँ।

2. संक्षेप में, पूर्ववर्ती बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 2 (डी. डी.) ने "निर्माण" शब्द को परिभाषित किया, जिसकी परिभाषा के तहत, "किसी भी वस्तु का मिश्रण" भी शामिल था। उक्त अधिनियम को तब पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके तहत "निर्माण" की परिभाषा को बदल दिया गया था, और "किसी भी सामान का मिश्रण" शब्द को हटा दिया गया था, हालांकि, "चाय का मिश्रण" अभी भी "निर्माण" की परिभाषा के तहत शामिल था। इसके अलावा, उक्त संशोधन के आधार पर, नए लघु औद्योगिक इकाइयों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कर छूट दी गई थी।

डी.

ई.

3. संशोधनों के बाद, बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुटीर और लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की राज्य योजना, 1993 में संशोधन किया गया था।

च

4. इस कर अवकाश के बाद, और इस तरह के कर अवकाश के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने मिश्रित चाय के निर्माण के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छोटे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की। अपीलार्थियों द्वारा इकाई की स्थापना के बाद, एक संशोधन के माध्यम से, "चाय का मिश्रण" शब्द को "निर्माण" की परिभाषा से हटा दिया गया था, जिससे अपीलार्थी को उक्त कर अवकाश का दावा करने से बाहर कर दिया गया था। यह इस बहिष्करण और चूक के खिलाफ है कि अपीलकर्ताओं ने दीवानी अपीलों का वर्तमान बैच दायर किया है।

जी.

एच.

840

5. वर्तमान मामले का एक विस्तृत तथ्यात्मक मैट्रिक्स मेरे सम्मानित भाई द्वारा उनकी राय में प्रस्तुत किया गया है, और संक्षिप्तता के लिए, मैं यहाँ उसी की नकल नहीं कर रहा हूँ।

विश्लेषण

6. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को बहुत विस्तार से सुना गया।

7. दीवानी अपीलों के वर्तमान समूह के माध्यम से, कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, और एक तैयार संदर्भ के लिए, दोनों मुद्दों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

**I. Whether** यहाँ अपीलार्थियों को अधिनियम के तहत बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा करने का निहित अधिकार है, क्योंकि अधिनियम की धारा **2 (170)** के तहत संशोधन किए जाने से पहले अपीलार्थियों पर निहित अधिकार अर्जित किया गया था?

ग

**II.** क्या वैध अपेक्षा का सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होता है क्योंकि अपीलकर्ताओं ने सरकार द्वारा दिए गए कर अवकाश के प्रलोभन के आधार पर अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की थी?

डी.

8. मैं पहले मुद्दे पर अपने सम्मानित भाई द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हूँ, और इसलिए, मेरी असहमति इस न्यायालय के समक्ष रखे गए दूसरे प्रश्न तक ही सीमित है।

ई.

कानून का नियम

9. कानून के शासन का सिद्धांत, एक आदर्श के रूप में, यह दर्शाता है कि एक राज्य को पुरुषों द्वारा नहीं, बल्कि कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए। यह अवधारणा अरस्तू के काम में अपनी उत्पत्ति पाती है, जहाँ वह टिप्पणी करते हैं कि एक ऐसे राज्य में जो न्याय और समानता के सिद्धांतों पर कार्य करता है, कानून का शासन सर्वोच्च होना चाहिए, और एक संस्था के रूप में राज्य को अपने शासक की सनक और कल्पनाओं के अधीन नहीं होना चाहिए।

च

10. जबकि कानून के शासन की उत्पत्ति प्राचीन यूनान से हुई है, कानून के शासन की आधुनिक अवधारणा, जो दुनिया भर में अधिकांश लोकतांत्रिक संविधानों का आधार है, प्रोफेसर ए. वी. डाइसी द्वारा लिखित पुस्तक "द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन" में अपनी जड़ें पाती है। 11. प्रोफेसर डाइसी, कानून के शासन के सिद्धांत की अपनी अवधारणा में, अरस्तू के विचारों को प्रतिध्वनित करते हुए कहते हैं कि सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को कानून के अधीन होना चाहिए, और यह कि कोई भी, यहां तक कि ए.

जी.

एच.

सरकार या उसके अधिकारी कानून से ऊपर हैं। कानून के इस तरह के कामकाज के लिए, डाइसी बताते हैं कि कानून स्पष्ट, स्पष्ट होना चाहिए और सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इस तरह की अवधारणा को आगे बढ़ाने और उस पर स्पष्टता लाने के लिए, प्रोफेसर डाइसी ने तीन सिद्धांतों पर स्पष्टीकरण दिया जो कानून के सुचारु अनुप्रयोग की विशेषता हैं।

12. पहला सिद्धांत, जो वर्तमान मामले के संदर्भ में सबसे अधिक प्रासंगिक है, वह आदर्श है कि कानून सर्वोच्च है, और कोई भी इकाई इसके ऊपर नहीं हो सकती है। इस सिद्धांत को पढ़ने का मतलब यह भी होगा कि कानून को सर्वोच्च होने के लिए, यह सभी पर लागू होना चाहिए, यह मनमाना नहीं हो सकता है, और न ही यह मनमाने तरीके से प्रदान की गई किसी भी चीज को छीन सकता है। सरल शब्दों में, कानून को सर्वोच्च होने के लिए, यह स्पष्ट होना चाहिए, और इसे अपने भीतर या बाहर की अन्य शक्तियों का शिकार हुए बिना अपने प्रति सच्चा रहना चाहिए।

ग

13. हमारे राष्ट्र के संदर्भ में कानून के शासन के इस सिद्धांत ने हमारे संविधान की मूल संरचना के भीतर शरण ली है। के मामले में

न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति बनाम भारत संघ और

ओआरएस। 1, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि कानून का शासन भारत के संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, इस संबंध में की गई प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

डी.

“दलीलों के गुण-दोष पर चर्चा करने से पहले न्यायपालिका और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अवलोकन करना आवश्यक है। इस क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए न्यायालय को एक ऐसा निर्माण अपनाना चाहिए जो संविधान की मूलभूत विशेषताओं और मूल संरचना को मजबूत करे। का नियम

ई.

कानून संविधान की एक बुनियादी विशेषता है जो पूरे संवैधानिक ताने-बाने में व्याप्त है और संवैधानिक संरचना का एक अभिन्न अंग है।”

च

14. यह कानून के शासन के इस सिद्धांत से है, क्या वैध अपेक्षा का सिद्धांत प्रवाहित होता है। जैसा कि नीचे विस्तार से वर्णित है, वैध अपेक्षा का सिद्धांत निकटता से जुड़ा हुआ है, और कानून के शासन के कामकाज के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून का शासन और वैध अपेक्षा दोनों ही कानूनी प्रणाली की निष्पक्षता और पूर्वानुमेयता के लिए आधार हैं। कानून के शासन का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कानून समान रूप से और लगातार लागू किए जाएं, जबकि वैध अपेक्षा का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अधिकारी उचित और लगातार कार्य करें।

जी.

1 (1991) 4 एससीसी 699

एच.

842

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में। एक साथ, ये सिद्धांत सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, और वे कानूनी प्रणाली में लोगों के विश्वास को बनाए रखने में मदद करते हैं।

### कानूनी अपेक्षा का दस्तावेज़

15. सरल शब्दों में, वैध अपेक्षा का सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण कोई वादा करता है या इस तरह से कार्य करता है जो किसी व्यक्ति या समूह को किसी विशेष परिणाम की उम्मीद करने के लिए प्रेरित करता है। यह सिद्धांत, जो कानून के शासन के सिद्धांत से प्रवाहित होता है, सार्वजनिक प्राधिकरणों की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और निरंतरता के विचार पर आधारित है।

ग

16. जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट परिणाम की वैध अपेक्षा की जाती है, तो उक्त सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्णय लेते समय उसके द्वारा बनाई गई ऐसी अपेक्षा को ध्यान में रखना आवश्यक है जो संबंधित व्यक्ति या समूह के हितों को प्रभावित करती है। यदि सार्वजनिक प्राधिकरण ऐसा करने में विफल रहता है, तो व्यक्ति या समूह को निर्णय को चुनौती देने और एक उपाय खोजने का अधिकार है, जैसे कि वैध अपेक्षा को लागू करने का आदेश, जैसा कि मामले में स्थिति है।

डी.

17. हैल्सबरी के लॉज ऑफ़ इंग्लैंड, चौथे संस्करण, खंड I (I) 151 में, वैध अपेक्षा की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है, और सुविधा के लिए, इसे यहाँ निकाला जा रहा है:

ई.

वैध अपेक्षाएँ। एक व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से व्यवहार किए जाने की वैध अपेक्षा हो सकती है, लेकिन एक प्रशासनिक प्राधिकरण हो सकता है, भले ही उसे निजी कानून में इस तरह का व्यवहार प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार न हो। अपेक्षा या तो प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व या वादे से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें एक निहित प्रतिनिधित्व भी शामिल है, या लगातार पिछले अभ्यास से। एक वैध अपेक्षा के अस्तित्व के कई अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं; यह न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति लेने का अधिकार दे सकता है; इसका मतलब यह हो सकता है कि प्राधिकरण को ऐसा करने को सही ठहराने के लिए सार्वजनिक नीति के किसी प्रमुख कारण के बिना अपेक्षा को विफल करने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए; या इसका मतलब यह हो सकता है कि, यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति की वैध अपेक्षा को विफल करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे मामले पर अभ्यावेदन करने का अवसर देना चाहिए। अदालतें भी, उदाहरण के लिए, लाइसेंस देने के मामलों में, मूल आवेदनों, नवीनीकरण और रद्द करने के लिए आवेदनों के बीच अंतर करती हैं; एक पक्ष जिसे लाइसेंस दिया गया है वह

च

जी.

एच.

843

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

एक वैध अपेक्षा है कि इसे तब तक नवीनीकृत किया जाएगा जब तक कि ऐसा न करने का कोई अच्छा कारण न हो, और इसलिए अनुदान के लिए केवल एक आवेदक की तुलना में अधिक प्रक्रियात्मक संरक्षण का हकदार हो सकता है।

18. यूनाइटेड किंगडम के न्यायालयों ने, वैध अपेक्षा के सिद्धांत की अवधारणा करते हुए, न्यायिक समीक्षा के अन्य प्रमुख पहलुओं को अपनाया है जैसे कि वेड्सबरी अनुचितता के मामले में

आर बनाम। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्तों ने एम. एफ. के.

एजेंट लिमिटेड **2** और आर. (बैनकोल्ट) बनाम के मामले में शक्ति का दुरुपयोग।

विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव) **3** न्यायसंगत ठहराने के लिए

वैध अपेक्षाओं का अस्तित्व और संरक्षण। **19.** वैध अपेक्षा शब्द का उपयोग पहली बार के मामले में किया गया था

ग

श्मिट बनाम गृह मामलों के राज्य सचिव **4** ब्रिटेन के न्यायालयों द्वारा।

हालाँकि, यह सिद्धांत उसके तथ्यों पर लागू नहीं किया गया था। इसके बाद, ओ 'रेली बनाम मैकमैन **5** के मामले में, वैध अपेक्षा के सिद्धांत को न्यायिक समीक्षा के लिए एक आधार के रूप में मान्यता दी गई, जिससे व्यक्तियों को इस आधार पर निर्णयों की वैधता को चुनौती देने की अनुमति मिली कि निर्णय निर्माता ने "उसे प्रदत्त शक्तियों के साथ काम किया था।"

डी.

**20.** इसके अलावा सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री **6** और आर बनाम उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य के मामलों में

प्राधिकरण, पूर्व पक्ष कफलान **7**, सिद्धांत की सीमाओं पर आगे विस्तार से बताया गया था। न्यायालयों के प्रयासों के बावजूद, वैध अपेक्षाएं कब उत्पन्न होती हैं, इस बारे में कुछ अस्पष्टता बनी रही, और इसके जवाब में, लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील, जॉन लॉज ने वैध लोगों के संरक्षण के लिए एक औचित्य के रूप में "अच्छे प्रशासन" की आकांक्षा का प्रस्ताव रखा।

ई.

नादराजा बनाम गृह विभाग के लिए राज्य सचिव **8** के मामले में अपेक्षाएँ।

च

**21.** वैध अपेक्षा के सिद्धांत को पहली बार भारतीय न्यायशास्त्र में केरल राज्य और अन्य बनाम अन्य के मामले में पेश किया गया था। के. जी. माधवन पिल्लई और अन्य। **9.** उपरोक्त मामले में, सरकार ने

**2** [1982] एसी 617

जी.

**3** [1990] 1 डब्ल्यूएलआर 1545 **4** [1969] 2 डब्ल्यूएलआर 337 **5** [1983] 2 एसी 237 **6** [1984] 3 डब्ल्यूएलआर 1174 **7** [2001] क्यू. बी.

**8** [2005] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 1363 **9** (1988) 4 एस. सी. सी. 669

एच.

**844**

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

उसमें प्रत्यर्थी के पक्ष में एक नया स्कूल खोलने और पहले से मौजूद कुछ स्कूलों को उन्नत करने के लिए मंजूरी जारी की गई। हालांकि, उपर्युक्त मंजूरी के बाद, सरकार द्वारा उक्त मंजूरी को स्थगित रखने के लिए एक नया निर्देश दिया गया था। उक्त मुद्दे का निर्णय करते समय इस न्यायालय की राय थी कि सरकार द्वारा दी गई मूल मंजूरी ने उत्तरदाताओं के मन में एक वैध अपेक्षा को जन्म दिया। हालाँकि इस वैध अपेक्षा का उल्लंघन स्थगन के लिए बाद के निर्देश द्वारा किया गया था, और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था। उक्त निर्णय से इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“...दूसरे शब्दों में, एक बार जब सरकार किसी मौजूदा गैर-सहायता प्राप्त स्कूल में एक नया गैर-सहायता प्राप्त स्कूल या उच्च वर्ग खोलने के लिए एक आवेदन को मंजूरी दे देती है और नियम 2-ए (5) के तहत एक आदेश पारित कर देती है, तो सफल आवेदक को एक नया स्कूल खोलने या मौजूदा स्कूल को अपग्रेड करने के लिए नियम 11 के तहत मंजूरी आदेश जारी करने के लिए नियम 9 और 11 के तहत अपने आवेदन पर आगे विचार करने का वैध अपेक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है, जैसा कि खंड पीठ ने बताया है कि नियम 2-ए (5) के तहत केवल अनुमोदन के अनुदान से, एक आवेदक को एक नया स्कूल खोलने या मौजूदा स्कूल को उन्नत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वह निश्चित रूप से नियम 11 के तहत विचार के अगले चरण में अपने आवेदन को ले जाने के लिए कानून में लागू करने योग्य अधिकार प्राप्त करता है। इसलिए खंड पीठ का यह विचार सही था कि केरल सामान्य खंड अधिनियम की धारा 20 के तहत राज्य सरकार को उपलब्ध रद्द करने की सामान्य शक्ति का निर्धारण "विषय वस्तु, संदर्भ और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के प्रभाव" के आलोक में किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

## 22. नवज्योति कूप में। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एंड ओआरएस बनाम संघ

भारत और ओआरएस। 10, आवास समितियों को भूमि के आवंटन के लिए मूल नीति वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित थी और उक्त नीति के तहत वरिष्ठता पंजीकरण की तारीख के आधार पर तय की गई थी। इसके बाद, मूल नीति में बदलाव किया गया, जिसमें वरिष्ठता तय करने के मानदंड को पंजीकरण की तारीख से अंतिम सूची के अनुमोदन की तारीख तक बदल दिया गया था। मूल नीति से उक्त विचलन को वैध अपेक्षा की कसौटी पर चुनौती दी गई थी

जी.

एच.

10 (1992) 4 एससीसी 477 ए

845

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

उसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा। इस न्यायालय ने उक्त चुनौती पर निर्णय लेते हुए कहा कि मूल नीति के साथ-साथ भूमि आवंटित करने की पिछली प्रथा ने पक्षकारों को आवंटन के एक अनुमानित पैटर्न की वैध अपेक्षा को जन्म दिया और नीति में नए परिवर्तन ने ऐसी वैध अपेक्षा को तोड़ दिया। उपर्युक्त निर्णय के माध्यम से इस व्याख्या ने वैध अपेक्षा के सिद्धांत की चौड़ाई को और बढ़ाया, और इसे न केवल एक स्पष्ट गारंटी तक बढ़ाया, बल्कि पिछले अभ्यास से उत्पन्न अपेक्षाओं तक भी बढ़ाया। तैयार संदर्भ के लिए उक्त निर्णय की प्रासंगिक टिप्पणियों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ हमें यह भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थिति में 20 जनवरी, 1990 के विवादित ज्ञापन में निहित नए नीतिगत निर्णय को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यदि आवश्यक हो तो समूह आवास समितियों को ज्ञात आवंटन के लिए मौजूदा मानदंड में इस तरह का बदलाव किए बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए था ताकि वे अपने विचारों पर विचार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व दे सकें। यह मानते हुए भी कि नाजुल नियमों के नियम 6 (vi) में "पहले आओ पहले पाओ" अभिव्यक्ति के किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में पंजीकरण की तारीख के संदर्भ में आवंटन करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी, वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि 20 जनवरी, 1990 के ज्ञापन में

निहित नए दिशानिर्देश से पहले आवंटन का सिद्धांत हमेशा पंजीकरण की तारीख के आधार पर था न कि सदस्यों की सूची के अनुमोदन की तारीख के आधार पर। 26 सितंबर, 1981 को नाज़ुल नियमों की राजपत्र अधिसूचना के बाद भी डी. डी. ए. द्वारा 1982 में जारी विवरणिका में पंजीकरण में वरिष्ठता के आधार पर आवंटन की नीति स्पष्ट रूप से इंगित की गई थी। उपरोक्त तथ्यों में, समूह आवास समितियां आवंटन के मामले में लगातार पिछले अभ्यास का पालन करने की 'वैध अपेक्षा' करने की हकदार थीं, भले ही उन्हें इस तरह का उपचार प्राप्त करने के लिए निजी कानून में कोई कानूनी अधिकार न हो। 'वैध अपेक्षा' के अस्तित्व के कई अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं और ऐसे परिणामों में से एक यह है कि प्राधिकरण को अपने ऐसा करने को सही ठहराने के लिए सार्वजनिक नीति के किसी प्रबल कारण के बिना 'वैध अपेक्षा' को हराने के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। 'वैध अपेक्षा' के मामले में यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति की 'वैध अपेक्षा' को विफल करने का प्रस्ताव करता है तो उसे मामले में अभ्यावेदन करने का अवसर देना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

846 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

इस संबंध में हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड, चौथी संस्करण के खंड 1 (1) के पृष्ठ 151 पर 'वैध अपेक्षा' पर चर्चा का संदर्भ दिया जा सकता है। (पुनः जारी करें)। हम सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री [(1984) 3 सभी ई. आर. 935] में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक व्यथित व्यक्ति न्यायिक समीक्षा का हकदार है यदि वह यह दिखा सकता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण के एक निर्णय ने उसे कुछ लाभ या लाभ से प्रभावित किया है जो अतीत में उसे प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी और जिसे वह वैध रूप से तब तक प्राप्त करने की अनुमति देने की उम्मीद करता था जब तक कि उसे वापस लेने का कारण और ऐसे कारणों पर टिप्पणी करने का अवसर नहीं दिया जाता।

ग

यहाँ यह संकेत दिया जा सकता है कि 'वैध अपेक्षा' का सिद्धांत संक्षेप में सार्वजनिक प्राधिकरण पर इस तरह की 'वैध अपेक्षा' से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य लागू करता है। 'वैध अपेक्षा' के मामले में निष्पक्ष लेन-देन के परिप्रेक्ष्य में, पक्षों द्वारा प्रतिनिधित्व करने के उचित अवसर सुसंगत पिछली नीति के किसी भी परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा एक नया दिशानिर्देश पेश करके पंजीकरण में वरिष्ठता के संदर्भ में आवंटन की मौजूदा नीति से हटने के लिए हमें कोई ठोस कारण नहीं दिखाया गया है। इसके विपरीत, विद्वान वकील श्री जेटली ने कहा है कि डी. डी. ए. और/या केंद्र सरकार का उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का कोई इरादा नहीं है और 20 जनवरी, 1990 के विवादित ज्ञापन को वापस ले लिया गया है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि मामले के तथ्यों में यह केवल वांछनीय था कि आवंटन के लिए दिशानिर्देश में किसी भी बदलाव को लागू करने या लागू करने से पहले, दिशानिर्देश में प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर पंजीकृत समूह आवास समितियों को, यदि आवश्यक हो, एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दिया जाना चाहिए था।"

डी.

ई.

च

जी.

23. वैध अपेक्षा का सिद्धांत तब आगे था

भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनू पशु आहार उद्योग 11 के मामले में विस्तार से बताया गया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि

एच.

11 (1993) 1 एससीसी 71 ए

847

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

सार्वजनिक प्राधिकरणों का उचित तरीके से कार्य करने का कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के उचित तरीके से व्यवहार किए जाने की वैध अपेक्षा रखने का अधिकार देता है। सार्वजनिक प्राधिकरणों पर निष्पक्ष तरीके से कार्य करने के लिए लगाई गई यह वैध अपेक्षा, जैसा कि माना गया है, राज्य की कार्रवाई की गैर-मनमानी सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। इस न्यायालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि ऐसी वैध अपेक्षा अपने आप में एक प्रवर्तनीय अधिकार नहीं हो सकती है, तथापि ऐसी अपेक्षा को ध्यान में रखने में विफलता सार्वजनिक प्राधिकरण के निर्णय को मनमाना मान सकती है। यह मेरी राय है कि इस न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त निर्णय, उल्लेखनीय रूप से कानून के शासन के सिद्धांत, वैध अपेक्षा के सिद्धांत और मनमानेपन के सिद्धांत को एक साथ बुनता है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के भीतर वैध अपेक्षा के सिद्धांत को दृढ़ता से जड़ देता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेदों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

ग

“हमारे विचार में, श्री ए. के. सेन अपनी प्रस्तुति के पहले भाग में सही हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी को वहाँ से कोई लाभ नहीं मिलता है। उच्च न्यायालय का निर्णय एकमात्र इस आधार पर आधारित है कि एक बार निविदा आमंत्रित किए जाने और निविदा सूचना में निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के आगे आने के बाद, सभी निविदाकारों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है और इस तरह उच्चतम निविदा को अस्वीकार कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय के अनुसार, इस तरह की प्रक्रिया कानून के शासन द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। यह श्री सेन के प्रस्तुत करने के समान नहीं है, जो कानून के शासन के एक आवश्यक सहवर्ती, गैर-मनमानेपन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निविदाएं प्राप्त करने के बाद बातचीत की प्रक्रिया पर स्विच करने का निर्णय लेते समय संकेतित केवल ठोस आधारों पर इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति तक सीमित है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्रस्ताव, जो उसके निर्णय का एकमात्र आधार है, स्वीकार्य होने के लिए बहुत व्यापक है और इसे आगे बताए गए तरीके से सीमित किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

संविदात्मक क्षेत्र में अन्य सभी राज्य कार्यों की तरह, राज्य और उसके सभी उपकरणों को संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें गैर-मनमानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक कानून में कोई निरंकुश विवेकाधिकार नहीं है: एक सार्वजनिक प्राधिकरण के पास केवल सार्वजनिक भलाई के लिए उनका उपयोग करने की शक्तियाँ होती हैं। यह निष्पक्ष रूप से कार्य करने और एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाने के कर्तव्य को लागू करता है जो 'कार्रवाई में निष्पक्षता' है। अच्छे प्रशासन के एक हिस्से के रूप में इस दायित्व का उचित पालन एक उचित या

जी.

एच.

प्रत्येक नागरिक में राज्य और उसके उपकरणों के साथ बातचीत में निष्पक्ष व्यवहार की वैध अपेक्षा, यह तत्व राज्य के सभी कार्यों में निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है। इसलिए, राज्य की कार्यवाही में गैर-मनमानी की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निर्णय से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की उचित या वैध अपेक्षाओं पर विचार करना और उन्हें उचित महत्व देना आवश्यक है या अन्यथा कि शक्ति के प्रयोग में अन्याय किसी दिए गए मामले में निर्णय की ईमानदारी को प्रभावित करने के अलावा अधिकार का दुरुपयोग या अधिकता के बराबर हो सकता है। इस प्रकार किए गए निर्णय को मनमानेपन के आधार पर चुनौती दी जाएगी। कानून का शासन शक्ति के प्रयोग में विवेक को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, क्योंकि यह अवास्तविक है, लेकिन न्यायिक समीक्षा द्वारा इसके प्रयोग पर नियंत्रण का प्रावधान करता है।"

ग

24. इसके अलावा, M.P.Oil निष्कर्षण और ए. एन. आर. बनाम के मामले में। राज्य

एम. पी. और अन्य। 12, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में संचालित होता है और इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक ठोस और प्रवर्तनीय अधिकार है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद को नीचे निकाला जा रहा है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"प्रत्यर्थियों के पक्ष में निष्पादित किए गए विवादित समझौतों में नवीकरण खंड भी अन्यायपूर्ण या अनुचित प्रतीत नहीं होता है। क्या समझौते की शर्तों के तहत साल के बीजों की आपूर्ति के माध्यम से संरक्षण को आगे की अवधि के लिए जारी रखने की आवश्यकता है, यह राज्य सरकार द्वारा निर्णय का विषय है और जब तक कि ऐसा निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है, तब तक न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मामले के तथ्यों में, राज्य सरकार के संरक्षण को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने के निर्णय को इस तरह के नीतिगत निर्णय की अतार्किक, मनमाना या मनमौजी न्यायिक समीक्षा नहीं माना जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने नवीकरण खंड की अयोग्यता के बारे में अपीलार्थी के तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया है। अपीलार्थी नवीकरण खंड सहित समझौते की वैधता को चुनौती देने के पहले के प्रयासों में विफल रहे। इसलिए, नवीकरण खंड की बाद की चुनौती पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सके कि तथ्य की स्थिति में ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि नवीकरण के मामले में विवेकाधिकार

ई.

च

जी.

एच.

12 (1997) 7 एससीसी 592 ए

849

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

राज्य द्वारा समझौते का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। डॉ. सिंघवी द्वारा यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता वैध रूप से उम्मीद करते हैं कि नवीनीकरण खंड को सामान्य तरीके से और पिछले अभ्यास के अनुसार प्रभावी किया जाना चाहिए जब तक कि इस तरह के अभ्यास का पालन न करने का कोई विशेष कारण न हो। "वैध अपेक्षा" के सिद्धांत को इस न्यायालय

द्वारा कई निर्णयों में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है। "वैध अपेक्षा" का सिद्धांत सार्वजनिक कानून के क्षेत्र में काम करता है और एक उपयुक्त मामले में, एक मूल और प्रवर्तनीय अधिकार का गठन करता है।"

25. जबकि उपर्युक्त निर्णय वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत की प्रयोज्यता की व्यापकता पर चर्चा करते हैं, हालाँकि, ऐसा अधिकार सभी को शामिल नहीं करता है, और इस तरह इसकी सीमाएँ हैं। यह इन प्रतिबंधों पर है, जैसा कि नीचे विस्तार से चर्चा की गई है, प्रतिवादी इस पर अपनी निर्भरता रखता है।

ग

26. एम. आर. एफ. लिमिटेड के मामले में कोट्टायम बनाम सहायक आयुक्त बिक्री कर और अन्य। 13, के सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए

डी.

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वैध अपेक्षा, चुनौती के लिए एक आधार के रूप में, उन परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती है जिनमें सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि उक्त अपेक्षा को वापस लेना जनहित के आधार पर किया गया है। सरल शब्दों में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सृजित वैध अपेक्षा पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जाती है।

ई.

"अनुच्छेद 14 और निष्पक्षता के नियम पर आधारित अंतर्निहित वैध अपेक्षा के सिद्धांत को फिर से व्यक्त किया गया है

बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा। बनाम वाणिज्यिक

कर अधिकारी और अन्य। 14, यह पैरा 8 और 9 में देखा गया था: "एक व्यक्ति को एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा एक निश्चित तरीके से व्यवहार किए जाने की 'वैध अपेक्षा' हो सकती है, भले ही उसे इस तरह का व्यवहार प्राप्त करने का निजी कानून में कोई कानूनी अधिकार न हो। अपेक्षा या तो प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व या वादे से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें एक निहित प्रतिनिधित्व भी शामिल है, या लगातार पिछले अभ्यास से। न्यायिक समीक्षा के विकासशील कानून में वैध अपेक्षा के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हालाँकि, इस मामले में सिद्धांत का पता लगाना आवश्यक नहीं है, यह केवल पर्याप्त है

च

जी.

13 (2006) 8 एस. सी. सी. 702

14 (2005) 1 एस. सी. सी. 625

एच.

850 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

ध्यान दें कि एक वैध अपेक्षा उस व्यक्ति को सक्षम करने के लिए पर्याप्त ब्याज प्रदान कर सकती है जो न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक ठोस अधिकार के अस्तित्व की ओर इशारा नहीं कर सकता है। आम तौर पर इस बात पर सहमति होती है कि 'वैध अपेक्षा' आवेदक को न्यायिक समीक्षा के लिए पर्याप्त अधिकार देती है और यह कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत ज्यादातर किसी निर्णय से पहले निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार तक ही सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप किसी वादे को नकार दिया जाता है या किसी वचन को वापस ले लिया जाता है। यह सिद्धांत प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे राहत का दावा करने की गुंजाइश नहीं देता है क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट अधिकार शामिल नहीं है। इस तरह की वैध अपेक्षा के संरक्षण के लिए अपेक्षा की पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, जहां एक प्रमुख सार्वजनिक हित की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, जहां किसी व्यक्ति की वैध अपेक्षा एक विशेष निर्णय लेने से पूरी नहीं होती है, तो निर्णय निर्माता को कुछ प्रमुख सार्वजनिक हित दिखाकर ऐसी अपेक्षा से इनकार करने को उचित ठहराना चाहिए। जबकि कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में

नीति को बदलने का विवेकाधिकार, जब किसी कानून या नियम द्वारा कुचला नहीं जाता है, तो अनुच्छेद 14 के संदर्भ में जो अनिवार्य और निहित है वह यह है कि नीति में परिवर्तन निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए और यह धारणा नहीं देनी चाहिए कि यह मनमाने ढंग से या किसी अन्य मानदंड द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 14 का व्यापक विस्तार और राज्य की गतिविधि के क्षेत्र की परवाह किए बिना इस कसौटी पर इसकी वैधता के लिए अर्हता प्राप्त प्रत्येक राज्य कार्रवाई की आवश्यकता एक स्वीकृत सिद्धांत है। अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता राज्य द्वारा कार्रवाई में निष्पक्षता है, और सार और सार में गैर-मनमानेपन निष्पक्ष खेल की दिल की धड़कन है। न्यायिक समीक्षा के परिदृश्य में कार्रवाई केवल इस हद तक उचित है कि राज्य को स्पष्ट कारणों से वैध रूप से कार्य करना चाहिए, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। मनमानेपन का अर्थ और वास्तविक महत्व और अवधारणा को सटीक रूप से परिभाषित करने की तुलना में अधिक आसानी से देखा जा सकता है। यह प्रश्न कि क्या विवादित कार्रवाई मनमाना है या नहीं, अंततः किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर जवाब दिया जाना है। ऐसे मामलों में लागू करने के लिए एक बुनियादी और स्पष्ट परीक्षण यह देखना है कि क्या आक्षेपित कार्रवाई से कोई स्पष्ट सिद्धांत उभर रहा है और यदि ऐसा है, तो क्या यह वास्तव में तर्कसंगतता की परीक्षा को संतुष्ट करता है।"

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

[जोर दिया गया] ए

851

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

एम. आर. एफ. ने केरल राज्य में एक वादे के तहत भारी निवेश किया कि उसे सात साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट दी जाएगी। इसे पात्रता प्रमाण पत्र दिया गया था। छूट का आदेश भी पारित किया गया था। जब राज्य सरकार ने एम. आर. एफ. द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास, श्रम और रोजगार में योगदान के रूप में किए गए निवेश से लाभ प्राप्त किया था और राज्य के हिस्से के रूप में राज्य के खजाने को भी एक बड़ा लाभ दिया था, तब राज्य सरकार के लिए चक्रवृद्धि रबर के संबंध में अपने पर्याप्त निवेश के संबंध में एम. आर. एफ. को कर छूट के लाभ से वंचित करने की अनुमति नहीं है। केरल राज्य में 177 करोड़ रु. राज्य सरकार की ओर से आक्षेपित कार्रवाई अत्यधिक अनुचित, अनुचित, मनमाना है और इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राज्य की कार्रवाई को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि यह मनमाना या अनुचित है। यह

ग

डी.

ई. पी. रोयप्पा बनाम में न्यायालय। तमिलनाडु राज्य **15**, मनाया गया

कि जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। राज्य द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप एक पक्ष के पक्ष में उत्पन्न होने वाली समानता "न्याय और निष्पक्ष खेल" की मूल अवधारणा पर आधारित है। आई. डी. 1 से छूट के उक्त लाभ को छीनने का प्रयास और इस तरह एम. आर. एफ. को कुल 7 वर्षों की अवधि में से 5 वर्षों से अधिक के लिए छूट के लाभ से वंचित करने

का प्रयास, हमारी राय में, अत्यधिक मनमाना, अन्यायपूर्ण और अनुचित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में राज्य सरकार के पास एस. आर. ओ. 1729/93 में पूर्वव्यापी संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, जो इसके तहत एम. आर. एफ. को पहले से प्राप्त अधिकारों को प्रभावित करता है।"

ई.

च

27. इसके अलावा, हावड़ा नगर निगम और अन्य के मामले में बनाम. गंगा रोप कंपनी लिमिटेड और अन्य। 16, यह इस द्वारा आयोजित किया गया था

जी.

न्यायालय ने कहा कि वैध अपेक्षा के आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है, जब उक्त अपेक्षा जनहित में लागू वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। इसी तरह, मद्रास शहर के शराब व्यापारियों के मामले में

15 (1974) 4 एससीसी 3 16 (2004) 1 एससीसी 663

एच.

852 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 8 एस. सी. आर.

एसोसिएशन और ए. एन. आर. बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्न। 17, यह आयोजित किया गया था

कि वैध अपेक्षा के सिद्धांत को उन मामलों में निष्क्रिय कर दिया जाता है जहां सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक हित के कारण सार्वजनिक नीति में परिवर्तन के माध्यम से उक्त अपेक्षा को रद्द कर दिया जाता है।

28. जबकि वैध अपेक्षा के सिद्धांत की सीमाओं पर उपर्युक्त निर्णयों को सरसरी रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि उक्त सिद्धांत नीति या वैधानिक परिवर्तन के खिलाफ उपलब्ध नहीं होगा, उसी का सावधानीपूर्वक अवलोकन अन्यथा दिखाएगा। वैध अपेक्षा का सिद्धांत कानून के शासन के सिद्धांत के भीतर अपना घर पाता है और यह अनुच्छेद 14 का एक अंग है जो मनमाने ढंग से राज्य की कार्यवाही और शक्ति के दुरुपयोग के संदूषण के खिलाफ लड़ता है। उपरोक्त सभी निर्णयों में जो वैध अपेक्षा की सीमाओं पर चर्चा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जनहित सर्वोच्च है।

ग

29. ऐसी परिस्थिति में, जब वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर सभी सीमाएं जनहित की कसौटी पर टिकी होती हैं, तो ऐसे मामलों में जहां वैध अपेक्षा की प्रयोज्यता को रोककर सार्वजनिक हित ही विफल हो जाता है, वैध अपेक्षा पर लगी रोक को हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसका यह भी अर्थ होगा कि वैध अपेक्षा के खिलाफ प्रतिबंध का दावा करने के लिए एक संशोधन के लिए, यह प्रदर्शित करना होगा कि नीति में उक्त परिवर्तन जनहित में किया गया था।

डी.

30. सरल शब्दों में, उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर, किसी कानून के खिलाफ वैध अपेक्षा का अनुमान लगाया जा सकता है, बशर्ते कि वैध अपेक्षा का ऐसा दावा सार्वजनिक हित में हो, और किसी कानून के लिए वैध अपेक्षा के खिलाफ प्रतिबंध का दावा करने के लिए, यह प्रदर्शित करना चाहिए कि नीति में बदलाव सार्वजनिक हित की उन्नति के लिए है।

ई.

31. यह स्पष्ट करने के लिए कि किसी कानून के खिलाफ वैध अपेक्षा के आह्वान पर इस तरह का प्रतिबंध कानून के शासन के विपरीत क्यों है, हमें पहले इस तरह की व्याख्या को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए। यदि उपरोक्त व्याख्या को अपनाया जाता है, तो राज्य, संशोधनों के माध्यम से, व्यक्तियों और संस्थानों को एक निश्चित परिणाम की उम्मीद के साथ एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए लुभा सकता है, और अचानक, जनहित के किसी भी प्रदर्शन के बिना, इसे रद्द कर सकता

है। यदि इस तरह के परिदृश्य को वास्तविकता में प्रकट होने दिया जाता है, तो यह कानूनी प्रणाली की किसी भी और सभी निश्चितता को हटा देगा, और सीधे कानून के शासन के खिलाफ हो जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी कानून के खिलाफ वैध अपेक्षा के सिद्धांत की अनुमति दी जानी है, तो कोई भी घरेलू या विदेशी निवेशक कभी भी स्थानीय निवेश में निवेश नहीं करेगा।

च

जी.

17 (1994) 5 एससीसी 509 ए

एच.

853

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

व्यवसाय और उद्यम, एक कानून के माध्यम से कोई भी वैध अपेक्षा केवल एक अग्रभाग में परिवर्तित होगी, क्योंकि इस तरह के लाभ को किसी भी समय मनमाने ढंग से छीन लिया जा सकता है। इसलिए, वैध अपेक्षा के सिद्धांत की कोई भी विपरीत व्याख्या, बहुत तबाही का कारण बनेगी, और केवल व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगी।<sup>32</sup> इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत और वचन रोधन का सिद्धांत दो अलग-अलग सिद्धांत हैं, और इस तरह, एक कानून के खिलाफ वचन रोधन पर पूर्ण प्रतिबंध वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर लागू नहीं हो सकता है।<sup>33</sup> प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत और वैध अपेक्षा का सिद्धांत, जबकि वे एक सामान्य जड़ और एक समान विषय साझा करते हैं, सामान्य कानून की कठोरताओं से गुजरने के माध्यम से, दो अलग-अलग सिद्धांतों में विकसित हुए हैं। निजी कानून में प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत एक उपाय है; हालाँकि, वैध अपेक्षा का सिद्धांत सार्वजनिक कानून में एक उपाय है, और जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है।

ग

डी.

34. सार्वजनिक कानून और निजी कानून के बीच इस तरह का अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक बार जब कोई कानून सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो यह समाज के अधिकारों को प्रभावित करता है, और इस प्रकार कड़ी स्तर की जांच के लिए उत्तरदायी हो जाता है, और इस तरह, न्यायिक समीक्षा के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है।

35. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, और वैध अपेक्षाओं के सिद्धांत के दायरे और सीमाओं में स्पष्टता लाने के लिए, मुझे वैध अपेक्षाओं के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को तैयार करना आवश्यक लगता है:

ई.

I. The अपेक्षा उचित होनी चाहिए: की उम्मीद

व्यक्ति या समूह को तर्कसंगत होना चाहिए और किसी मनमाने या तर्कहीन आधार पर आधारित नहीं होना चाहिए। अपेक्षा एक स्थापित प्रथा या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किए गए स्पष्ट वादे पर आधारित होनी चाहिए।

च

II. अपेक्षा एक स्पष्ट प्रतिनिधित्व पर आधारित होनी चाहिए:

अपेक्षा सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किए गए स्पष्ट और स्पष्ट प्रतिनिधित्व पर आधारित होनी चाहिए।

जी.

III. प्रतिनिधित्व एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए

व्यक्ति:प्रतिनिधित्व सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर किसी अधिकृत व्यक्ति या निकाय द्वारा किया जाना चाहिए।प्राधिकरण के पास इस तरह का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति और क्षमता होनी चाहिए।

#### IV. प्रतिनिधित्व वैध होना चाहिए:प्रतिनिधित्व

एच.

सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किया गया कार्य वैध होना चाहिए और इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए।

854

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 8 एस सी आर।

कोई भी कानून या नीति।यह किसी भी जनहित या सार्वजनिक नीति के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए।

#### V. जनहित का प्रदर्शन किया जाना चाहिए:यदि वैध है

सार्वजनिक हित के आधार पर मौजूदा नीति में संशोधन के माध्यम से अपेक्षा को दूर किया जा रहा है, ऐसे सार्वजनिक हित को उक्त संशोधन द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

#### VI. सार्वजनिक हित को नीति में बदलाव का स्थान लेना चाहिए:मामलों में

जहाँ नीति में संशोधन के माध्यम से एक वैध अपेक्षा को दूर किया जा रहा है, वहाँ ऐसा संशोधन सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा संशोधन सार्वजनिक हित के विपरीत है, तो वैध अपेक्षा का उपाय प्रयोग करने योग्य हो जाएगा।

ग

#### VII. अपेक्षा वैध ब्याज पर आधारित होनी चाहिए:

अपेक्षा व्यक्ति या समूह के वैध हित पर आधारित होनी चाहिए।यह किसी निहित स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ पर आधारित नहीं होना चाहिए।

डी.

#### VIII. अपेक्षा की रक्षा की जानी चाहिए:एक बार वैध

अपेक्षा बनाई जाती है, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा मनमाने ढंग से या मनमौजी रूप से वापस नहीं लिया जाना चाहिए।सार्वजनिक प्राधिकरण को अपेक्षा को वापस लेने या संशोधित करने का कोई भी निर्णय लेने से पहले व्यक्ति या समूह को सुनने का एक उचित अवसर प्रदान करना चाहिए।

ई.

वर्तमान फैक्टुअल मैट्रिक्स में कानूनी अपेक्षाओं का अनुप्रयोग

36. पश्चिम बंगाल बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 52 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 17 (3) (1) (xi) के साथ पठित बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 (इसके बाद '1941 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 39 के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए चाय के निर्माण में शामिल नई लघु औद्योगिक इकाइयों को कर छूट दी गई थी।

च

37. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में, वैधानिक रूप से, चाय के मिश्रण को "निर्माण" की परिभाषा के तहत पढ़ा जाता था, और इस तरह, चाय के मिश्रण में शामिल छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों पर भी कर अवकाश लागू था।

जी.

38. इस तरह की कर छूट दिए जाने के बाद, अपीलकर्ताओं ने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन और विश्वास पर भरोसा करते हुए, लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की और उन्हें प्रमाणित करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त किए। हालाँकि, पश्चिम बंगाल वित्त अधिनियम, 2001 में एक संशोधन के माध्यम से, "चाय का मिश्रण" शब्दों को हटा दिया गया था।

एच.

855

मेसर्स के. बी. टी. ए. प्रोडक्ट पी. वी. टी. लिमिटेड. वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिलिगुड़ी [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

"विनिर्माण" की परिभाषा से, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी कर अवकाश के तहत लाभ का दावा करने के लिए अपात्र हो गए। 39. तथ्यों की समझ से, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चाय के निर्माण और मिश्रण में शामिल लघु उद्योगों को एक संशोधन के माध्यम से दी गई कर छूट ने यहां अपीलार्थियों के पक्ष में एक वैध अपेक्षा पैदा की। एक संशोधन के माध्यम से बनाई गई इस तरह की वैध अपेक्षा ने अपीलार्थियों को इस धारणा के तहत लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में अपनी मेहनत की कमाई डालने के लिए लुभाया कि प्राधिकरण अपने वादे को पूरा करेगा, निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा और उसके द्वारा किए गए निर्णय का पालन करेगा।

40. उपयुक्त और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई गई इस वैध अपेक्षा को तब तोड़ा गया जब बाद में एक संशोधन लाया गया, जिसमें "चाय का मिश्रण" शब्दों को "निर्माण" की परिभाषा से हटा दिया गया था। उक्त शब्दों को हटाकर इस तरह के संशोधन ने एक विशिष्ट परिणाम की वैध अपेक्षा को छीन लिया और अपीलार्थियों को कर अवकाश का दावा करने से वंचित कर दिया, जिसके लिए उन्हें मूल संशोधन द्वारा वादा किया गया था। जैसा कि देखा जा सकता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक उचित वैध अपेक्षा बनाई गई थी, जिसने अपीलार्थियों को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए लुभाया। इस तरह की वैध अपेक्षा को तब छीन लिया गया, जिससे अपीलार्थी बिना उपचार के और नुकसान में रह गए।

ग

डी.

41. नीति में इस तरह के बदलाव को उचित ठहराने के लिए, और अपीलकर्ताओं के पक्ष में बनाई गई वैध अपेक्षा को छीनने के लिए, सार्वजनिक प्राधिकरण को इस तरह के बदलाव के कारणों को प्रदर्शित करना चाहिए, और अपना औचित्य देते समय, प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, और सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के लिए ऐसे अधिकारों को छीनना क्यों आवश्यक है।

ई.

च

42. वर्तमान मामले में, बाद के संशोधन के माध्यम से अध्ययन करते हुए, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा ऐसा कोई उचित औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। संशोधन के अधिनियमन के लिए कोई उचित कारण नहीं है और न ही प्रभावित पक्ष के विचारों पर चर्चा की गई है। मेरी राय में, नीति परिवर्तन का केवल दावा सरकार में निहित सबूत के बोझ को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को सटीक रूप से दिखाना चाहिए कि नीति में परिवर्तन क्या है, और कानून में इस तरह का परिवर्तन सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ाने में क्यों है।

जी.

43. इसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स और उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक वैध अपेक्षा थी

एच.

856

लोक प्राधिकारी द्वारा सृजित और इसमें अपीलार्थियों के पक्ष में उपाजित ऐसी अपेक्षा को उक्त प्राधिकारी द्वारा लोक हित के किसी भी प्रदर्शन के बिना रद्द कर दिया गया था। इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कानून में बदलाव क्यों किया गया था, और अपीलार्थियों और समान रूप से स्थित व्यक्तियों को होने वाले नुकसान के बावजूद, सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का बदलाव क्यों आवश्यक था। ऐसी परिस्थिति में, अपीलार्थियों के मन में उत्पन्न वैध अपेक्षा की रक्षा की जानी चाहिए, और मूल रूप से दिए गए लाभों को प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा वादा की गई अवधि के लिए अपीलार्थियों पर लागू किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

ग

44. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वैध अपेक्षा का सिद्धांत अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा सिद्धांत, जो कानून के अनुप्रयोग में पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करता है, अपने सार में, कानून के शासन के क्षरण के खिलाफ लड़ता है, और मनमानी राज्य कार्रवाई को रोकता है।

डी.

45. एक लोकतांत्रिक राज्य को समानता और न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करने के लिए, राज्य को उसके शासक द्वारा नहीं, बल्कि कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में, कानून के शासन के इस तरह के संदूषण को रोकने के लिए, वैध अपेक्षा के सिद्धांत का अनुप्रयोग सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि किसी राज्य को वादे करने की अनुमति दी जाती है, और बिना किसी औचित्य या स्पष्टीकरण के उन्हें रद्द कर दिया जाता है, तो यह ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिसमें राज्य का हर कार्य जवाबदेही से वंचित होगा, और इस देश के कानूनों द्वारा शासित प्रत्येक व्यक्ति भय और अशांति की स्थिति में रहेगा, जिससे लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर एक भयावह प्रभाव पड़ेगा। 46. इसलिए, मेरी राय है कि वर्तमान मामले में, प्राधिकरण को उसके द्वारा बनाई गई वैध अपेक्षा के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और इसलिए, मूल संशोधन के अनुसार इस तरह के लाभ की समाप्ति तक, इसमें मूल संशोधन के लाभों को अपीलार्थियों तक बढ़ाने के लिए उत्तरदाताओं को एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए। उसी के आलोक में, दीवानी अपीलों के वर्तमान बैच की अनुमति है।

ई.

च

जी.

दिव्या पांडे

माननीय सीजेआई के समक्ष रखे जाने वाले मामले।

(सहायक: अभिषेक अग्निहोत्री और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

एच.